

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

चेन्नई कस्टम्स पर उगाही का आरोप, विनट्रेक कंपनी ने शटर डाउन किया, केंद्र सरकार ने दिए सख्त जांच आदेश

Publisher

Published on 03 Oct 2025



लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। विनट्रेक इंक. नामक कंपनी ने चेन्नई कस्टम्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारत में अपना आयात-निर्यात परिचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि लगातार हो रही उगाही और उत्पीड़न के कारण उसके लिए कामकाज जारी रखना मुश्किल हो गया था। इस फैसले से लॉजिस्टिक्स और व्यापार जगत में हलचल मच गई है।

विनट्रेक इंक. का आरोप है कि चेन्नई कस्टम्स के अधिकारियों द्वारा बार-बार अनुचित मांगों की जा रही थीं। कंपनी प्रबंधन का दावा है कि वैध आयात-निर्यात कागजों के बावजूद उनसे अतिरिक्त भुगतान की मांग की जाती थी। लगातार बढ़ते दबाव और उत्पीड़न ने आखिरकार कंपनी को भारत में अपना परिचालन बंद करने पर मजबूर कर दिया।

यह मामला केंद्र सरकार के संज्ञान में पहुंचते ही बड़ा रूप ले चुका है। वित्त मंत्रालय ने तुरंत राजस्व विभाग को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की निगरानी एक वरिष्ठ अधिकारी करेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम संकेत देता है कि भ्रष्टाचार या उत्पीड़न के मामलों को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कंपनी के शटर डाउन करने से उन व्यापारियों और उद्योगपतियों की चिंता भी बढ़ गई है, जिनके उत्पादों की दुलाई और निर्यात-आयात विनट्रेक के जरिए होती थी। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस घटना ने उन मुश्किलों को और गहरा कर दिया है।

सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कंपनी को अनुचित दबाव या उगाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल के वर्षों में 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। ऐसे में यह घटना

उन प्रयासों पर सवाल खड़े करती है और सरकार के लिए चुनौती भी है कि वह पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करे।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के मामले समय पर सख्ती से निपटाए न जाएं तो इसका असर भारत की वैश्विक छवि पर पड़ सकता है। भारत तेजी से विश्व व्यापार और निवेश का केंद्र बन रहा है। ऐसे में विदेशी और घरेलू कंपनियों को भरोसा दिलाना बेहद जरूरी है कि उनकी सुरक्षा और व्यावसायिक स्वतंत्रता सरकार की प्राथमिकता है।

विनट्रैक इंक. का यह फैसला केवल एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता अभी भी बाकी है। खासकर लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। सरकार ने इस दिशा में कई डिजिटल उपाय लागू किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और उगाही की शिकायतें अब भी समय-समय पर सामने आती रहती हैं।

जानकारों का मानना है कि यह घटना आने वाले समय में सुधारों की नई श्रृंखला की शुरुआत कर सकती है। सरकार शायद कस्टम्स विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और निगरानी प्रणालियों को लागू करे। इसके अलावा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

चेन्नई जैसे बड़े पोर्ट पर कामकाज ठप होने या विवाद बढ़ने से न केवल स्थानीय व्यापार प्रभावित होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी प्रभावित करता है। भारत में आयात-निर्यात कारोबार की रीढ़ लॉजिस्टिक्स सेक्टर है और इसका किसी भी तरह से कमजोर होना पूरे उद्योग जगत के लिए हानिकारक है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और अगर किसी भी अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि भारत में कारोबार करने वाले सभी निवेशकों और कंपनियों का भरोसा बरकरार रहे।

कुल मिलाकर, विनट्रैक और चेन्नई कस्टम्स विवाद ने यह साफ कर दिया है कि भारत के कारोबारी माहौल में सुधार की यात्रा अभी अधूरी है। लेकिन केंद्र सरकार का त्वरित हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में यह मामला न केवल भारत की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बल्कि वैश्विक निवेशकों के विश्वास पर भी असर डाल सकता है।